भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1479

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम-ई-बस सेवा योजना की स्थिति

1479. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-ई-बस सेवा योजना की स्थिति क्या है और उक्त योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत तैनात की गई इलेक्ट्रिक बसों की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत संवितरित की गई निधियों का राज्यवार और वर्षबार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेलंगाना और विशेष रूप से हैदराबाद में उक्त योजना के अंतर्गत कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): 14 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के शहरों के लिए 7293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। बिजली और सिविल डिपो के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 983.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 66 शहरों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 563.34 करोड़ रुपए और 64 शहरों में सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 420.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाना संबंधित डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पीएम-ई-बस सेवा टेंडर में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर निर्भर है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 437.50 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं (ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया हैं)।

(ग): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, तेलंगाना के वारंगल और निज़ामाबाद नामक दो शहर क्रमशः 100 और 50 ई-बसों के लिए पात्र हैं। हालाँकि, इन शहरों ने इस योजना में भाग नहीं लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है, इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

*****

अनुलग्नक-I

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी पहली किश्त (करोड़ रुपए में)	वर्ष
1	बिहार	87.55	वित्तीय वर्ष 2024-25
2	गुजरात	9.06	
3	चंडीगढ़	11.87	
4	असम	6.47	
5	छत्तीसगढ	30.18	
6	महाराष्ट्र	200.18	
7	ओडिशा	47.72	
8	राजस्थान	44.46	
	कुल	**437.50 रु.**	